छत्तीसगढ़

सहकारी समाचार

वर्ष- 22 अंक - 10 अगस्त 2025 द्वितीय अंक (पाक्षिक) RNI NO. CHHHIN/2012/45105 पृष्ठ-12 मूल्य 500/- वार्षिक

सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ आगे बढ़ें : राज्यपाल

राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के समापन अवसर पर शामिल हुए राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर। रायपुर में आयोजित दो दिवसीय सहकार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन में राज्यपाल श्री रमेन डेका शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे।

सहकार भारती द्वारा राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में 23 और 24 अगस्त को देश में पहली बार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि, सहकारिता के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बुनकरों से आव्हान किया कि वे समयानुसार उत्पादों में नवीन तकनीकों को अपनाएं। मांग के अनुसार उत्पादों के डिजाइन में बदलाव लाएं। राज्यपाल ने कहा कि, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल सहकारिता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर विश्व की नींव रखना है। यही भावना हमें प्रेरित करती है कि हम 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ आगे बढ़ें और इस अभियान को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं।

देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि, सहकारिता हमारे रग-रग में बसी हुई है। हम सब 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से पले-बढ़े हैं। भारत अपने कुटीर उद्योगों और ग्राम उद्योगों की बदौलत लंबे समय तक पूरी दुनिया के लिए 'सोने की चिड़िया' था। उन्होंने कहा कि, देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान है। हमारे बुनकर बड़ी मेहनत और लगन से कपड़ा उद्योग को मजबूती दे रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नए आयाम दिए जा सकते हैं। आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, देश को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने में बुनकर और उनकी सहकार की भावना काफी अहम है।

सहकार से समृद्धि के तहत राज्य में हुए हैं पहल : केदार कश्यप

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, यह गर्व का विषय है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में यह अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सहकार से समृद्धि के तहत राज्य में 54 पहल किए गए हैं जो सीधे-सीधे गांवों, गरीबों व किसानों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि, राज्य में लगभग 20 हजार हाथकरघा कार्यरत हैं जिनके माध्यम से 60 हजार 300 लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य में 329 पंजीकृत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां महासंघ से जुड़ी हुई हैं जो सरकारी वस्त्र उत्पादन में सक्रिय हैं। महासंघ द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को स्कूल यूनिफार्म, पुलिस ड्रेस, कंबल, चादर और अन्य प्रकार के कपड़ों की आपूर्ति की जा रही है। बुनकर सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में भी सहकारी नीति तैयार की जा रही है। श्री कश्यप ने सहकार भारती के पदाधिकारियों को अधिवेशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, इस अधिवेशन से बुनकरों में जागरूकता बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने नया दृष्टिकोण दिया

उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ ने सहकारिता के क्षेत्र में कई नवाचार कर देश को एक नया दृष्टिकोण दिया है। पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय बनाने का कार्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में अब तक 2058 पैक्स समितियों को एम-पैक्स में परिवर्तित किया गया है और इनमें कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही 532 नई बहुउद्देशीय पैक्स समितियों के गठन की प्रक्रिया जारी है। मत्स्य, दुग्ध और लघु वनोपज क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो सहकारिता के विस्तार की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सीएम साय के वीडियो संदेश का हुआ प्रसारण

उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

बुनकरों के हित में हो रहे अच्छे कार्य : लखनलाल देवांगन

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि, बुनकर समाज बड़ी लगन और मेहनत के साथ कार्य करते हैं। बुनकर आदिकाल से बुनकरी के माध्यम से कपड़ा निर्माण का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बुनकरों के हित में अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बुनकरों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। हमने बुनकरों के सम्मेलन में बुनकरों की मजदूरी बढ़ाने की बात कही थी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तत्काल बुनकरों की मजदूरी 20 प्रतिशत बढ़ा दी, जिसका 60 हजार लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

ढाई करोड़ लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े : राष्ट्रीय महामंत्री

सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री दीपक कुमार चौरसिया ने अधिवेशन में कहा कि, सहकारिता व्यक्ति के संघर्ष को शक्ति देता है। इससे आर्थिक विकास के साथ ही इंसान को सबल होने का मौका मिलता है। बुनकर परंपरा, संस्कृति और आजीविका को जोड़ता है। देश में करीब ढाई करोड़ लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। इस अधिवेशन से उनकी सामाजिक-आर्थिक चेतना को जगाने का काम होगा। उन्होंने बताया कि भारत से हर वर्ष साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के कपड़ों का निर्यात होता है। इसमें 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बुनकरों के काम का है।

सहकार भारती देश के 28 राज्यों में कर रही काम : राष्ट्रीय अध्यक्ष

सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता लोगों का स्थायी आर्थिक विकास करता है। सहकार भारती देश के 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 650 जिलों में काम कर रही है। पिछले दो वर्षों में अलग-अलग प्रकोष्ठों द्वारा 12 राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। इस अधिवेशन में बुनकरों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा तैयार कर सरकार से बात करेंगे। यहां देशभर के अलग-अलग बुनकर संघ अपने कार्यों, समस्याओं और भविष्य के बारे में विचार-विमर्श कर आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे।

इनकी भी रही मौजूदगी

सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर, राष्ट्रीय बुनकर प्रकोष्ठ के प्रमुख अनंत कुमार मिश्र, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी, अधिवेशन संयोजक सुरेन्द्र पाटनी, सह-संयोजक पुरुषोत्तम देवांगन, व्यवस्था प्रमुख अजय अग्रवाल, स्वागत समिति की सदस्य शताब्दी पाण्डेय और प्रीतपाल बेलचंदन सहित सहकार भारती के अन्य पदाधिकारी तथा सहकारिता व ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी भी उद्घाटन सत्र में मौजूद थे।

कपड़ों, हस्तशिल्प और वनोत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री भी

अधिवेशन स्थल में विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े, हस्तशिल्प से निर्मित सामग्रियों और वनोत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं।

वर्ष 2024 में डीसीसीबी और राज्य सहकारी बैंकों का प्रदर्शन रहा शानदार

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में बताया कि, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में वित्तीय मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। लघुकालीन सहकारी ऋण संरचना में 34 राज्य सहकारी बैंकों की 2,140 शाखाएँ, 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 13,759 शाखाएँ और लगभग 1.06 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ शामिल हैं। सामूहिक रूप से ये संस्थाएँ करीब 6.5 लाख गाँवों को सेवा देती हैं और ग्रामीण ऋण आपूर्ति की रीढ़ हैं।

राज्य सहकारी बैंकों की अंश पूंजी 10,531 करोड़ रुपये पहुंची

राज्य सहकारी बैंकों की अंश पूँजी 7.7% बढ़कर 10,531 करोड़ रुपये हो गई, जबकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 8.2% वृद्धि के साथ 28,661 करोड़ रुपये पहुँची। भंडार भी बढ़कर क्रमशः 22,861 करोड़ रुपये और 31,701 करोड़ रुपये हो गए। जमा राशि में स्थिर वृद्धि हुई-राज्य सहकारी बैंकों ने 2,56,819 करोड़ रुपये (6% वृद्धि) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 4,76,610 करोड़ रुपये (10% वृद्धि) जुटाए।

32 राज्य सहकारी बैंकों 2,691 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया

34 राज्य सहकारी बैंकों में से 32 ने 2,691 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 9.5 % अधिक है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में लाभ कमाने वाले बैंकों की संख्या 305 से बढ़कर 312 हो गई और शुद्ध लाभ 14.5% बढ़कर 3,297 करोड़ रुपये हो गया। हालाँकि घाटा झेलने वाले जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की हानि 1,403 करोड़ रुपये रही, लेकिन नुकसान उठाने वाले बैंकों की संख्या घटी।

उधारी और निवेश में भी हुई बढ़ोतरी

उधारी और निवेश में भी बढ़ोतरी हुई। राज्य सहकारी बैंकों की उधारी 11.7 % बढ़कर 1,73,100 करोड़ रुपये और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 9.9 % बढ़कर 1,61,700 करोड़ रुपये रही। निवेश क्रमशः 1,55,800 करोड़ रुपये और 2,65,700 करोड़ रुपये तक पहुँचे। राज्य सहकारी बैंकों के बकाया ऋण 10.9% बढ़कर 2,94,577 करोड़ रुपये और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 11.4% बढ़कर 4,13,161 करोड़ रुपये तक पहुँचे। इसके परिणामस्वरूप कुल परिसंपत्ति/देयताएँ राज्य सहकारी बैंकों की 4,88,266 करोड़ रुपये और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 7,65,577 करोड़ रुपये दर्ज हुई।

क्रेडिट-टू-डिपॉजिट अनुपात में आया सुधार

क्रेडिट-टू-डिपॉजिट अनुपात (ऋण-जमा अनुपात) राज्य सहकारी बैंकों में 114.7% और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 86.7% तक सुधरा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) क्रमशः 12.9% और 11.9% तक मामूली घटा। परिसंपत्ति गुणवत्ता बेहतर हुई। सकल अक्रिय परिसंपत्तियाँ (एनपीए) राज्य सहकारी बैंकों में घटकर 4.9% और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 8.9% पर आ गई। शुद्ध एनपीए क्रमशः 2.0% और 3.4% रहे।

सहकारी बैंक दुर्ग से 720.28 करोड़ का ऋण स्वीकृत

दुर्ग। अभिजीत सिंह, कलेक्टर दुर्ग एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की अध्यक्षता में 21 अगस्त को ऋण उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संचालक सहकारी सदस्य अवधेश मिश्रा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग, संदीप कुमार भोई, उप संचालक संचालक कृषि जिला दुर्ग एवं सचिव के रूप में एसके जोशी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग उपस्थित थे।

बैठक में कुल 309 प्रकरणों की राशि 720.28 करोड़ ऋण स्वीकृत किये गये। जिसमें फसल ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 से 2027-28 कुल 2 समितियों के लिए राशि 113.06 लाख, उद्यानिकी फसल केला ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के 5 प्रकरणों में राशि 7.28 लाख, पपीता ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 अंतर्गत 3 प्रकरणों में राशि 8.28 लाख, टमाटर ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 अंतर्गत 3 प्रकरणों में राषि 6.69 लाख, करेला ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 अंतर्गत 1 प्रकरणों में राशि 0.80 लाख स्वीकृत की गई है।

इन ऋण प्रकरणो को भी मिली मंजूरी

गौ पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीन के 153 प्रकरणों में राशि 269.90 लाख एवं नवीनीकरण के 97 प्रकरणों में 158.69 लाख, मत्स्य पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण के 01 प्रकरणों में 0.78 लाख, बकरी पालन हेतु नवीन केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के 4 प्रकरणों में राशि 5.52 लाख, कुकुट पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण के 2 प्रकरणों में राशि 6.00 लाख, मध्यमकालीन नार्मल ऋण 7 वर्ष अंतर्गत 4 प्रकरणों में राशि 6.23 लाख, मध्यकालीन व्यक्तिगत ऋण के 17 प्रकरण में राशि 84.95 लाख, गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत नगद साख सीमा नवीन के 1 प्रकरणों में राशि 5.00 लाख, गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत नगद साख सीमा पुनः स्वीकृति 2 प्रकरणों में राशि 10.00 लाख, स्वयं सहायता समूह ऋण स्वीकृति पश्चात पुष्टि हेतु 8 प्रकरणों में राशि 7.10 लाख, स्वयं सहायता समूह ऋण स्वीकृति हेतु 3 प्रकरणों में राशि 7.60 लाख, स्वयं सहायता समूह एन.आर.एल.एम. अंतर्गत 1 प्रकरण में राशि 1.50 लाख, धान खरीदी केन्द्र में कम्प्यूटर कक्ष, बोर पंप हेतु ऋण स्वीकृति अंतर्गत 1 प्रकरण में राशि 15.90 लाख की स्वीकृति दिया गया। बैठक में बैंक अधिकारी सुश्री कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक एवं श्री एसपी वाहने शाखा प्रबंधक उपस्थित रहें।

रामकिशुन राम और जुगनी बाई की जिंदगी में फिर से लौटी खुशियाँ

जशपुरनगर। प्रकृति की मनमोहक ध्वनियाँ, अपने बच्चों और परिवारजनों की मधुर आवाजें जीवन को सुखद, जीवंत और आनंद से परिपूर्ण बना देती हैं। लेकिन जब सुनने की शक्ति छिन जाती है तब जीवन का ये संगीत जैसे थम सा जाता है। ऐसा ही कुछ बीता विकासखंड दुलदुला के ग्राम बोईडांड के रहने वाले बुजुर्ग रामकिशुन राम और जुगनी बाई के साथ।

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, दोनों की श्रवण क्षमता धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई। रामकिशुन राम ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें दोनों कानों से स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है। इस वजह से उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस समस्या से निजात पाने हेतु श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने की मांग की।

इसी प्रकार जुगनी बाई ने भी कैंप कार्यालय में आवेदन देकर अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उन्हें भी दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे इस समस्या से राहत पा सकें और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनके आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की और उन्हें श्रवण यंत्र प्रदान किया। अब रामकिशुन राम और जुगनी बाई फिर से सुन सकते हैं हर वो ध्वनि, अपने बच्चों, परिवारजनों की आवाज जो उनके जीवन को उमंग और आनंद से भर सकती है। श्रवण यंत्र पाकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और कैंप कार्यालय का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा मेरी समस्या का इतने जल्दी समाधान हो जाएगा यह सोचा नहीं था। आज मेरे जीवन में फिर से उजाला लौट आया है। गरीबों को मदद करने की संवेदनशील सोच और समय पर उनका काम बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बगिया में कैंप कार्यालय की नींव रखी, जहां कई जरूरतमंदों को सही समय में मदद मिल रही है।

सहकारिता आयुक्त कुलदीप शर्मा ने किया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर का औचक निरीक्षण

- उपस्थित खातेदारों एवं हितग्राहियों से चर्चा कर बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की ली जानकारी
- खातेदारों 10 हितग्राहियों को एटीएम कार्ड प्रदान कर डिजिटल लेनदेन के किया प्रोत्साहित

जगदलपुर। सहकारिता विभाग के आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान बैंक में उपस्थित खातेदारों एवं हितग्राहियों से चर्चा कर बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। श्री शर्मा ने इस मौके पर 10 हितग्राहियों को ए.टी.एम. कार्ड प्रदान कर उन्हें डिजिटल लेनदेन हेतु प्रोत्साहित किया। आयुक्त श्री शर्मा ने "सहकार से समृद्धि" अभियान के अंतर्गत "एक पेड़ माँ के नाम" पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश भी दिया।

निरीक्षण उपरांत श्री शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना, कॉमन सर्विस सेंटर की कार्यप्रगति, माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन की स्थिति, नवीन दुग्ध, मत्स्य, महिला, बहुउद्देशीय समितियों के गठन, कृषक उत्पादक समिति की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आयुक्त श्री शर्मा ने इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण एवं शुल्क वसूली, परिसमापनाधीन समितियों के अंतिम निराकरण की स्थिति तथा मुख्यालय से प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन की स्थिति की समीक्षा करते हुए सरकार की मंशानुरूप "सहकार से समृद्धि" अभियान के लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इस अवसर पर बस्तर संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री बिनोद कुमार बुनकर सहित बस्तर और कांकेर जिले के उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और जिला कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, अपेक्स बैंक के प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी तथा संबंधित जिला स्थित बैंको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त प्रबंधक व नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ में बदल रही ज़िंदगियाँ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित घर मिल रहे हैं। इस योजना ने गरीब और कमजोर वर्ग के जीवन में नई रोशनी लाई है। सक्ती जिले के विकासखंड सक्ती अंतर्गत ग्राम नंदौरखुर्द निवासी श्री लतेल दास महंत इसका जीवंत उदाहरण बने हैं।

कृषि कार्य से गुजर-बसर करने वाले श्री लतेल दास महंत वर्षों तक खपरैल वाले कच्चे मकान में रहते थे। बरसात के मौसम में टपकती छत, दरकती दीवारें और हर साल खपरैल पलटने की चिंता उनका सबसे बड़ा संकट था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह पक्का मकान बना पाने असमर्थ था।

प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने आवेदन किया और पात्रता मिलने के बाद उन्हें पक्का मकान आवंटित हुआ। आज उनका मजबूत, सुरक्षित आवास तैयार है, जिससे बरसात की परेशानियाँ अब इतिहास बन चुकी हैं। श्री लतेल दास महंत ने बताया कि हर साल बरसात हमारे लिए चिंता और संकट लेकर आती थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का घर हमें न सिर्फ सुरक्षा दे रहा है बल्कि आत्मसम्मान और स्थिरता भी प्रदान कर रहा है।

यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आए बदलाव को दर्शाती है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता और उसकी जमीनी हकीकत को बया कर रहा है। योजना ने छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान कर, सुरक्षित और स्थायी आवास देकर सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार प्रदान किया है।

सूरजपुर के गाँवों में लौटी सौर ऊर्जा की रोशनी

- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से ग्रामीणों के घरों में उजाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती अंचलों में अब अंधकार नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा की नई रोशनी गाँव-गाँव जगमगा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से सूरजपुर जिले के ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या से राहत मिली है।

महुली ग्राम के स्कूलपारा, चौरा पारा और खास पारा में स्थापित 10-10 किलोवॉट क्षमता वाले सौर संयंत्रों की बैटरियाँ बदली गई। इन संयंत्रों के शत-प्रतिशत कार्यशील होने से अब 150 से अधिक परिवारों के घरों में पूरी रात बिजली उपलब्ध है। बच्चों को पढ़ाई के लिए उजाला मिल रहा है, महिलाएँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं और गाँव की गतिविधियाँ रात तक सुचारू रूप से चल रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ÷सभी के लिए ऊर्जा÷ नीति के तहत स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ग्रामीण अंचलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से इसी दिशा में अब बाँकी और खोड़ जैसे गाँवों में भी सुधारात्मक कार्य प्रारंभ किया गया है। यहाँ 07 सौर संयंत्रों के लिए 372 नई बैटरियों की स्थापना की जा रही है, जिससे सैकड़ों परिवार लाभान्वित होंगे। भटगांव विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 60 लाख रुपये की लागत से इन्वर्टर और बैटरियाँ स्वीकृत हुई हैं। यह कार्य विशेष रूप से तमोर पिंगला अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र जैसे दूरस्थ वनांचलों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। यहाँ के ग्रामीणों को पहली बार स्थायी और भरोसेमंद बिजली सुविधा मिलेगी। यह पहल केवल तकनीकी सुधार भर नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम है, जो ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही है।

श्रवणदोष से पीड़ित चाका बाई को मिला श्रवण यंत्र

रायपुर। 90 वर्षीय चाका बाई की चेहरे से झलकती मुस्कराहट बता रही है कि उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई है। उम्र के इस दौर में शारीरिक परेशानियों का आना स्वाभाविक है और ऐसे समय में की गई सहायता बुजुर्गों के लिए बड़ी सहारा बनती है। जशपुर जिले के 90 वर्षीय चाका बाई ठीक से सुनाई नहीं देने की समस्या से जूझ रही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें उनकी परेशानियों का समाधान यहां पर अवश्य मिलेगा और हुआ भी ऐसा ही, कैंप कार्यालय से उन्हें तत्काल मदद मिली और उसे श्रवण यंत्र प्रदान किया गया।

ग्राम पंचायत जामचुआं, तहसील कुनकुरी निवासी चाका बाई ठीक से सुनाई नहीं देने की समस्या से जूझ रही थी। उन्होंने कैंप कार्यालय में आवेदन देकर अपनी समस्याओं को साझा किया। कैंप कार्यालय ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही की और उन्हें श्रवण यंत्र प्रदान किया।

श्रवण यंत्र पाकर चाका बाई ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को आशीर्वाद दिया है। गरीबों को मदद करने की संवेदनशील सोच और समय पर उनका काम बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बगिया में कैंप कार्यालय की नींव रखी, जहां कई जरूरतमंदों को सही समय में मदद मिल रही है और उनका जीवन सुधर रहा है।

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम ढुरकाबेड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 14 अगस्त 2025 को किया गया। जिसमें महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य ,सदस्यता सदस्य के अधिकार, कर्तव्य बैठकें, बैंक लिंकिंग, व्यवसाय विकास, मछली पालन, बकरी पालन, गाय पालन आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया। जिसे सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

रजत जयंती से स्वर्ण जयंती तक की यात्रा में मील का पत्थर है सहकारिता

रायपुर। रजत जयंती से स्वर्ण जयंती तक की यात्रा में मील का पत्थर है सहकारिता उक्त विचार 29 अगस्त 2025 को ग्राम बिरगुड़ी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में मुख्य अतिथि अकबर कश्यप ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से दी जा रही जानकारी का लाभ उठाना चाहिए। औषधीय पौधों की पहचान और खेती हमें संपन्नता दिला सकती है। जैविक खेती आज की मांग है। इस प्रशिक्षण सत्र का आयोजन जिला सहकारी संघ द्वारा जिले के समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियो व वनधन विकास केंद्र सहकारी समितियो के पदाधिकारियों, सदस्यों व प्रबंधकों का एकदिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन साहू समाज भवन ग्राम बिरगुड़ी में संपन्न हुआ।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष 2025 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अकबर कश्यप पूर्व अध्यक्ष जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित धमतरी, कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय शुभम यदु सभापति (सहकारिता एवं उद्योग) जनपद पंचायत नगरी, विशिष्ट अतिथि जिला लघु वनोपज धमतरी के संचालक राजेश कुमार सामरथ, साहू समाज बिरगुड़ी अध्यक्ष भूपत कुमार साहू, प्रवक्ता डॉक्टर एन दीक्षित, जिला सहकारी संघ धमतरी के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू तथा डॉक्टर अनिल चौरे, सुरेश साहू उपस्थित थे।

कार्यक्रम अध्यक्ष श्री यदु ने कहा कि सहकारिता ने आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाया है। ग्रामीण परिवेश में चहुमुखी सुधार हेतु सहकारिता सशक्त माध्यम है। श्री सामरथ ने कहा कि प्रशिक्षण से हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री साहू ने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में हमारी योजना है कि हमें 2025 के लक्ष्य के लिए कार्य करना है। नशा मुक्त छत्तीसगढ़ हमारा लक्ष्य है। देश का युवा निरोगी व संस्कारी हो। प्रवक्ता डॉक्टर दीक्षित ने अपने उद्बोधन में सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने, सहकार से समृद्धि के तहत 54 पहलो पर प्रकाश डाला। सुरेश साहू ने सहकारिता के उद्देश्य व महत्व के साथ ही शासन की योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथि डॉ चौरे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में मंचस्थ अतिथियों को श्रीफल व शाल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वनोपज समितियो के प्रबंधको सहित बड़ी संख्या में सहकारी समितियो के पदाधिकारी व सदस्य का उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रतावा व घोटगांव के समिति प्रबंधक ललित कश्यप का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन संघ प्रबंधक ए पी गुप्ता व आभार प्रदर्शन बेलरगांव समिति प्रबंधक रमेश पटेल ने किया।

दर्रीपारा कुटमा में छोटे बच्चों के लिए पीएम जन-मन आंगनबाड़ी बनकर तैयार

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को केन्द्र शासन और राज्य शासन की सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में विकास खंड बगीचा के ग्राम दर्रीपारा पारा कुटमा में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बसाहटों में नन्हें मुन्ने बच्चों के लिए सर्व सुविधायुक्त पीएम जनमन आंगनबाड़ी केन्द्र बनकर तैयार हो गया है।

जहां विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के बच्चें उत्साह से आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ने पहुंच रहे हैं।

जिला प्रशासन की पहल से बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त पीएम जनमन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।

महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल पीएम जनमन योजना के तहत 17 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई है।

इनमें बगीचा विकास खंड में 16 आंगनबाड़ी केंद्र और मनोरा विकास खंड में 1 आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल है।

इन आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन गर्म भोजन, स्वास्थ्य जांच, बच्चों का बौद्धिक विकास और प्रारंभिक शिक्षा का लाभ मिल रहा है।

पहारू राम ने कहा नए घर ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी

जशपुरनगर। बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत पंड्रापाठ के निवासी श्री पहारु राम वर्षो से कच्चे मकान में रहकर जीवनयापन कर रहे थे। बरसात के दिनों में छत टपकना, सर्दियों में ठंड से बचाव की समस्या और गर्मियों में तपन सहना उनके परिवार की मजबूरी बन गई थी। सीमित संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए केवल एक सपना था।

वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास की स्वीकृति मिली। समय पर राशि और सामग्री की उपलब्धता के कारण उनका मकान तैयार हुआ और अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित पक्के घर में रह रहे हैं। श्री पहारु राम बताते हैं कि नए घर ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। उनके अनुसारअब मेरे परिवार को मौसम की मार से बचाव मिल रहा है। यह घर हमारे लिए सुरक्षा और सम्मान की नई पहचान है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है।

ई-रिक्शा से बनी आत्मनिर्भर गायत्री

रायपुर। केन्द्र सरकार की लखपति दीदी योजना महिलाओं के जीवन में बदलाव के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से जुड़कर आज जिले की ग्रामीण महिलाओं ने स्वावलंबन की नित नई मिसाल पेश कर रही है। जिसकी एक बानगी ओटेबाधा की श्रीमती गायत्री यादव के रूप में देखने को मिली।

विकासखंड अंबागढ़ चौकी के जय माँ रानी दुर्गावती समूह ओटेबांधा की श्रीमती गायत्री यादव समूह से जुड़ने के साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त होने एवं नवाचार की उनकी सोच ने उन्हें ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके पति का सहयोग भी मिला। यात्रियों को उनके मंजिल तक छोड़ने वाले ई-रिक्शा आज श्रीमती यादव के लिए स्वावलंबन का हमसफर बन चुका है। आज उनकी मेहनत रंग लाई और श्रीमती यादव आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ ही लखपति दीदी बन चुकी है। इस बदलाव के माध्यम से उनके जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। समूह के माध्यम से लाभ प्राप्त कर श्रीमती यादव अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है।

लखपति दीदी श्रीमती यादव ने बताया कि इस योजना से अब वह न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है बल्कि योजना से मिली राशि व जिला प्रशासन से मिले सहयोग से आज वह स्वयं का व्यवसाय कर रही है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा स्व-रोजगार मार्गदर्शन भी प्रदान किए गए। योजना अंतर्गत ऋण राशि स्वीकृत की गई, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिली। आज उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। श्रीमती यादव कहती है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजनाए उन जैसी सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। वे अपने परिवार को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक तंगी से उबार रही है, और अपने आस-पास की महिलाओं लिए प्रेरणास्रोत भी बन रही है। उन्होंने योजनाओं क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र बना ग्रामीण विकास का नया आधार

रायपुर। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र ग्रामीण अंचलों के लिए आशा का नया आधार बन रहे हैं। कोरबा जिले के ग्राम बेला में प्रारंभ हुआ यह केन्द्र ग्रामीणों को शहर जाने की परेशानी से मुक्त कर, समय, धन और श्रम की बचत करा रहा है। इस केन्द्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, दस्तावेज़ सत्यापन, पेंशन वितरण, शासकीय योजनाओं का लाभ, कार्ड निर्माण सहित सभी कार्य गांव में ही हो रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा वर्ग इन सेवाओं का सहज रूप से उपयोग कर रहे हैं।

ग्राम बेला निवासी श्री धनीराम कंवर बताते हैं कि केन्द्र खुलने से अब पैसे निकालने या शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए बालको या अन्य शहर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने इसी केन्द्र से आयुष्मान भारत कार्ड भी बनवाया है, जिससे अब बड़े अस्पतालों में निःशुल्क उपचार संभव होगा। उनकी पत्नी, जो महतारी वंदन योजना की हितग्राही हैं, कहती हैं कि अब योजना की राशि सीधे केन्द्र से प्राप्त हो जाती है। इससे समय और पैसे की बचत होती है तथा घर-परिवार की देखभाल भी आसानी से हो जाती है।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का उद्देश्य ग्रामीणों को शहरों के बजाय गांव में ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह केन्द्र स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। प्रशिक्षित ऑपरेटरों के माध्यम से सभी कार्य शीघ्र और पारदर्शी ढंग से किए जा रहे हैं। कोरबा जिले के इन केन्द्रों से पेंशनधारियों को समय पर पेंशन मिल रही है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सीधे खाते में मिल रही है और निकासी का कार्य गांव से ही हो रहा है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि समय पर मिल रही है। साथ ही ग्रामीणों के आयुष्मान भारत कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज़ भी यहीं बन रहे हैं। ग्राम बेला सहित आसपास के गांवों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र ने लोगों का जीवन सरल बना दिया है। यह केन्द्र ग्रामीणों को तकनीकी रूप से सशक्त कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रहा है।

मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से दुर्योधन राम को मिलेगा नया सहारा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से दुर्योधन राम की जिंदगी एक बार फिर नई मुस्कान से भर उठेगी। लगभग 10 वर्ष पूर्व हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दुर्योधन का दायां पैर काटना पड़ा था। यह घटना उनके लिए एक बड़ा सदमा थी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्हें रायपुर इलाज के लिए भेजने का निर्णय लिया है, जहां दुर्योधन को कृत्रिम पैर लगाया जाएगा।

मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले ग्राम बोकी कारीताला निवासी दुर्योधन के लिए यह दुर्घटना मानो जीवन पर पहाड़ टूटने जैसा थी। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अच्छे अस्पताल में इलाज कराना उनके लिए बेहद कठिन था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उन्हें कृत्रिम पैर मिल सके ताकि उसे अपने कामकाज में आसानी हो। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यथा साझा की और कृत्रिम पैर लगवाने का निवेदन किया। आवेदन पर संजीदगी से संज्ञान लेते हुए कैंप कार्यालय ने तुरंत पहल की और उन्हें इलाज हेतु रायपुर भेजने का प्रबंध किया।

अपनी खुशी व्यक्त करते हुए दुर्योधन राम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आम जनता की तकलीफों को अपना समझते हैं। कैंप कार्यालय हमेशा ही आम आदमी की मदद के लिए तत्पर रहता है।

कैंप कार्यालय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझते लोगों को मिलती है तत्काल मदद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निजी निवास बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आमजन के लिए उम्मीद और सहारा का केंद्र बन चुका है। यहां स्वास्थ्य की समस्या से जूझते बगिया पहुंचने वाले जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद भी सुनिश्चित की जाती है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुलभ, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन की शुरुआत की है। यह हेल्पलाइन सेवा जिले के उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों या इलाज के अभाव में परेशान थे।

सीएम कैंप कार्यालय बगिया में प्राप्त आवेदन अनुसार अब तक इस पहल के अंतर्गत 2,856 मरीजों को इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सकीय सलाह, दवाइयाँ, अस्पताल में भर्ती की सुविधा, रेफरल सेवा और आवश्यकतानुसार एंबुलेंस की व्यवस्था कराई जा चुकी है।

बांस शिल्पकला बनेगा कमार और बसोड परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया

रायपुर। बांस शिल्प को आजीविका से जोड़कर कमार और बसोड परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वन विभाग द्वारा पारंपरिक बांस आधारित शिल्पकला एवं बांस आभूषणों के निर्माण संबंधी कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन बारनवापारा में किया जा रहा है। वन मण्डलाधिकारी बलौदाबाजार गणवीर धम्मशील के मार्गदर्शन में असम गुवाहाटी के बांस कला विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 36 हितग्राहियों को 02 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें ग्राम बल्दाकछार से 06, ठाकुरदिया से 14 एवं बारनवापारा से 16 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका के संसाधनों में पारंपरिक मूल्यों को संजोकर वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के पश्चात हितग्राही परिवारों द्वारा निर्मित बांस के आभूषणों एवं शिल्पकला को प्रदेश के साथ-साथ देश के विभिन्न स्थानों पर भी इसे विक्रय करने की योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण का आयोजन हितग्राहियों को दक्ष करने के साथ- साथ विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

दोकड़ा में दो विकास कार्यों के लिए 1.15 करोड़ की राशि स्वीकृत

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में सुशासन तिहार का तीसरा चरण सकारात्मक बदलावों का प्रतीक बनता जा रहा है। सुशासन तिहार के अवसर पर ग्राम दोकड़ा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आगमन पर उनके द्वारा घोषित दो विकास कार्यों के लिए 01 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि की स्वीकृत प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय के घोषणा के अनुरूप ग्राम दोकड़ा में जिन विकासकार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें ग्राम दोकड़ा में मंगल भवन के जीर्णोद्धार हेतु 20.00 लाख रुपए और कल्याण आश्रम भवन निर्माण के लिए 95.00 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माँझीपारा के विद्यालय को मिला खेवइया, यहाँ के विद्यार्थी बनेंगे पढ़इया

रायपुर। विष्णुदेव सरकार की शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की नीति ने आज कोरबा जिले के माझीपारा के मछुआ परिवारों के विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को नई दिशा दे दी है । कोरबा शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पाली विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगा नाला में बड़ी संख्या में मांझी परिवार निवास करते हैं। नाव चलाने, मछली बेचने सहित मजदूरी कर अपना आजीविका चलाने वाले इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने शासन ने इनके बसाहट के पास ही प्राथमिक शाला प्रारंभ किया। अन्तिम छोर वाले इस गाँव के पाठशाला में पिछले कई साल से विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से नियमित शिक्षक नहीं थे। शिक्षको की कमी की वजह से माँझीपारा के बच्चों की पढ़ाई तो जारी थी लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि मानो जिस नाव रूपी प्राथमिक शाला में वे सवार है वह मझधार में फंसी हुई है। उन्हें मंजिल तक पहुंचाने एक और खेवइया रूपी शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। राज्य शासन की युक्ति युक्तकरण की पहल ग्राम पंचायत डोंगा नाला माँझीपारा के पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए बड़ी वरदान बनकर आई। यहाँ एक और शिक्षिका की नियुक्ति हो जाने से मानो स्कूल को एक और खेवइया मिल गया है, जो इन्हें मंजिल तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण मददगार साबित होगा।

माँझीपारा में पांचवीं तक पाठशाला खुले हुए 21 साल हो गए, लेकिन यहाँ बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की कमी कभी न कभी बनी ही रही। शिक्षको की कमी की वजह से इस स्कूल से वास्ता रखने वाले माँझी जाति के लोगो के बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता था। समस्या सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों तक की ही नहीं थीं, उनके पालकों की भी थी। उन्हें भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। इस बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अपनाई गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से माँझीपारा के प्राथमिक शाला में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के साथ ही स्कूल की भी भाग खुल गई। स्कूल में जहाँ दो नियमित शिक्षक हो गए, वही यहाँ पदस्थ हुई शिक्षिका नई मैडम के रूप में दिन भर विद्यार्थियों के जुबान में बस गई है। पाठशाला खुलते ही मैडम के आने और कक्षा में पढ़ाने की चर्चा तो विद्यार्थी करते ही है, मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं।

पाली ब्लॉक के अंतर्गत दूरस्थ ग्राम पंचायत डोंगानाला के अंतर्गत अंतिम छोर पर बड़ी संख्या में मांझी परिवार निवास करते हैं। मांझी परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नजदीक ही प्राथमिक शाला का संचालन शासन द्वारा किया जाता है। प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक श्री मणि दास मानिकपुरी ने बताया कि विद्यालय वर्ष 2004 से संचालित है। वर्तमान में 50 विद्यार्थी अध्ययनरत है। उन्होंने बताया कि आसपास के गरीब परिवार के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ाई करने आते हैं। यहां नियमित शिक्षक की कमी बनी हुई थी। युक्ति युक्तकरण से हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका की नियुक्ति की गई है। नई शिक्षिका के आने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत मदद मिली है। इधर क्लास ले रही नई शिक्षिका राजश्री लहरे से विद्यार्थी भी घुले-मिले नजर आ रहे थे। ब्लैकबोर्ड पर लिखकर अभ्यास में जुटी शिक्षिका को पाकर कक्षा दूसरी की सिमरन, बृज कुमारी ,कक्षा पांचवीं की सती कुमारी, प्रियांशी सहित अन्य विद्यार्थियों में खुशी का वातावरण है। वे बताती है कि नई मैडम अच्छी लगती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सहकारी संस्थाएं हो रही है सहकार से समृद्ध

मालगांव के किसानों ने लिया सहकारी प्रशिक्षण

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ रायपुर के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मालगांव के किसानों ने सहकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया। सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद जाती द्वारा किसानों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, बैठक का महत्व, आम सभा, सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य, सहकारी कर्ज नीति, सहकारिता से समृद्धि, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति तथा लाल क्रांति के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का समापन 21 अगस्त 2025 को किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में लेखपाल श्री लोचन जोशी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर रोहित पांडे का विशेष सहयोग रहा।

धनियालुर के ग्रामीणों को मिला सहकारी प्रशिक्षण

जगदलपुर। बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड की धनियालुर ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर एवं बस्तर जिला सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर के तत्वाधान में 13 अगस्त को पंचायत भवन में आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे के द्वारा ग्रामीण कृषक सदस्यों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत के साथ-साथ शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया व गाय पालन के लिए सहकारी बैंक से ऋण लेने आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और किसान क्लब बनाकर सभी लोग अच्छे से खेती करने के लिए व बोर खनन आदि शासकीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित बस्तर जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री सी. के द्विवेदी के द्वारा समिति के गठन पंजीयन आदि विषय पर विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने में ग्राम धनियालुर के सरपंच एवं उपसरपंच का सहयोग रहा साथ ही संघ के रोमांचल पाणिग्राही का विशेष सहयोग रहा।

पैक्स कंप्यूटरीकरण में महाराष्ट्र अव्वल, लद्दाख सबसे पीछे

रायपुर। ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत 30 जून 2025 तक देशभर की 73,492 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को कम्प्यूटरीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। सहकारिता मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर की संस्थाओं में पारदर्शिता, दक्षता और सुलभता लाना है।

महाराष्ट्र इस सूची में सबसे आगे है, जहाँ 12,000 पैक्स को स्वीकृति मिली है। इसके बाद राजस्थान (7,468), गुजरात (5,754), उत्तर प्रदेश (5,686) और कर्नाटक (5,682) प्रमुख राज्यों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश (5,188), तमिलनाडु (4,532) और बिहार (4,495) भी मजबूत भागीदारी दिखा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल (4,167) और पंजाब (3,482) शीर्ष दस में जगह बनाए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ के 2,028 पैक्स समितियों को मिली मंजूरी

ओडिशा हाल ही में इस परियोजना से जुड़ा है और यहाँ 2,711 पैक्स को स्वीकृति मिली है। आंध्र प्रदेश (2,037), छत्तीसगढ़ (2,028), झारखंड (2,797) और हिमाचल प्रदेश (1,789) में भी पर्याप्त स्वीकृतियाँ दी गई हैं। हालाँकि, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में काफी पीछे हैं। गोवा (58), अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (46), पुदुच्चेरी (45), मिजोरम (49), अरुणाचल प्रदेश (14), लद्दाख (10) और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (4) की स्थिति न्यूनतम है। यह आँकड़े उनके सीमित सहकारी ढाँचे और भौगोलिक चुनौतियों को दर्शाते हैं।

पैक्स मे इआरपी-आधारित सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा

परियोजना के अंतर्गत पैक्स में ईआरपी-आधारित सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, जिससे रीयल-टाइम अकाउंटिंग, ऋण वितरण और जिला व राज्य सहकारी बैंकों से एकीकरण संभव होगा। पैक्स अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि बदलाव सुगमता से लागू हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े ग्रामीण अर्थतंत्र वाले राज्य जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को निकट भविष्य में सबसे अधिक लाभ होगा, वहीं छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि सहकारी डिजिटलीकरण की इस यात्रा में कोई भी क्षेत्र पीछे न रह जाए।

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के बकावंड ब्लॉक के ग्राम सोनपुर के पंचायत भवन में कृषक सदस्य भाइयों का सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा दिनांक 20 व 21 अगस्त 2025 को किया गया। जिसमें सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत उद्देश्य, उद्भव विकास, सदस्यता सदस्य के अधिकार कर्तव्य, बैठके, आमसभा, ऋणनीति, व्यवसाय विकास आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया।

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के बकावंड ब्लॉक के ग्राम पहुरबेल के पंचायत भवन में कृषक सदस्य भाइयों का सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा दिनांक 22 व 23 अगस्त 2025 को किया गया । जिसमें सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य उद्भव और विकास सहकारी ढांचा सदस्यता सदस्यता के अधिकार, कर्तव्य, बैठकें, आमसभा, ऋणनीति, पंजीयन व्यवसाय विकास आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया। जिसे सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

अंधेरे से उजाले की ओर, लामपहाड़ में शिक्षा की नई भोर

युक्तियुक्तकरण से शिक्षकविहीन विद्यालय लाम पहाड़ प्राथमिक शाला में शिक्षक की हुई नियुक्ति

कोरबा । कुछ समय पहले लाम पहाड़ का नाम सुनते ही एक कठिन राह पर मुश्किल सफ़र का दृश्य उभर कर आँखों में छा जाता था। पहाड़ो में बसाहट होने और यहाँ तक पहुचने में अनेक चुनौतियां होने की वजह से यहाँ रहने वाले पहाड़ी कोरवाओं को कई सुविधाओं से महरूम होना पड़ता था। अब जबकि बिजली,पानी और सड़क के साथ इस बसाहट में स्कूल बनकर संचालित हो रहा है तो लाम पहाड़ क्षेत्र के पहाड़ी कोरवाओं के बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अन्धकारमय जीवन से बाहर निकलकर शिक्षा के भोर के सहारे बेहतर भविष्य गढ़ने का अवसर मिल गया है। यहाँ आवागमन सहित अन्य चुनौतियों की वजह से शिक्षकविहीन की श्रेणी में आने वाले लामपहाड़ के पाठशाला को शासन की युक्ति युक्तकरण की पहल ने न सिर्फ नियमित शिक्षक की सौगात दी अपितु यहाँ पढ़ाई करने आने वाले बच्चों के भविष्य की राह भी आसान कर दी है।

कोरबा विकासखंड अंतर्गत अन्तिमछोर के ग्रामपंचायत बड़गांव के आश्रित ग्राम लामपहाड़ की पहचान भले ही अब कठिन राह पर मुश्किल सफ़र की नहीं रही, लेकिन बड़ी संख्या में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा ही यहाँ की पहचान अभी भी है। शहर से बहुत दूर घने जंगलों के आसपास निवास करने वाले पहाड़ी कोरवाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने शासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ विद्यालय का संचालन कर पहाड़ी कोरवा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की पहल की गई, लेकिन विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका के पदोन्नति होकर अन्यत्र स्थानान्तरण के बाद विगत कुछ वर्षों से नियमित शिक्षक नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को उठाना पड़ता था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अतिशेष शिक्षको के समायोजन व युक्ति युक्तकरण की पहल ने यहाँ की तस्वीर बदलने का काम किया। यहाँ संचालित प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला में शिक्षको की पदस्थापना होने से अब यह विद्यालय शिक्षकविहीन की श्रेणी से बाहर आ गया है। नियमित शिक्षक के नियुक्ति से पहाड़ी कोरवा विद्यार्थियों की पढ़ाई भी नियमित होने लगी है। यहाँ जाने पर युक्ति युक्तकरण से प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक श्री कलेश्वर राम कटेला क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाई कराते नजर आए। उन्होंने बताया कि युक्ति युक्तकरण से लामपहाड़ के प्राथमिक शाला को दो और माध्यमिक शाला को एक शिक्षक मिले हैं। प्राथमिक शाला में कुल 33 बच्चे और मिडिल स्कूल में 19 बच्चे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भरत लाल के लिए बनी सहारा

रायपुर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में किसानों को दी जाती है। इसी क्रम में सक्ती जिले के ग्राम पंचायत अचानकपुर अंतर्गत ग्राम डड़ाई निवासी किसान श्री भरतलाल राठौर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। इस योजना से उन्हे आर्थिक सम्बल मिला है। किसान भरतलाल ने बताया कि इस सहायता राशि का उपयोग खाद-बीज की खरीद और कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे करते हैं तथा अन्य तात्कालिक जरूरतों के लिए उपयोग कर रहे है। श्री भरत लाल ने बताया कि पहले की तरह अब हम किसानों को अपनी खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और वे आत्मनिर्भर होकर कृषि कार्य कर रहे है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह योजना सभी किसानों के लिए बहुत हितकारी है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से उपभोक्ताओं को मिल रही राहत

रायपुर। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब उपभोक्ताओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने आगे आ रहे हैं। ऐसे ही बिलासपुर जिले के ग्राम कोनी के निवासी श्री रमेश साहू ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इसके बाद उनका बिजली बिल शून्य हो गया है।इस अभिनव योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

कोनी में रहने वाले श्री रमेश साहू बताते हैं कि उनके घर पर बिजली की खपत काफी अधिक थी प्रतिमाह आने वाले बिजली के बिल से उन्हें बड़ा आर्थिक भार झेलना पड़ता था। सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जिसकी लागत करीब दो लाख रुपए थी। इस प्लांट पर उन्हें केन्द्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिल चुकी है, जबकि राज्य सरकार से मिलने वाली 30 हजार रुपये की सब्सिडी भी शीघ्र मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बिजली बिल की चिंता से मुक्ति मिल गई है।अब उन्हें किसी तरह का बिल नहीं भरना पड़ रहा। एक बार निवेश करने पर 25 वर्षों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है और इस पर कोई विशेष मेंटेनेंस खर्च भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में सप्लाई कर आय अर्जित करने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में यह योजना बड़ा कदम है। श्री साहू ने आम नागरिकों से अपील की कि वे भी इस योजना का लाभ उठाएं और सौर ऊर्जा को अपनाकर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनें।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर केन्द्र सरकार से 78 हजार रुपये तक सब्सिडी और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही सरकार 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। योजना में घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा मिलती है जिससे बनने वाली खपत से अतिरिक्त बिजली ग्रिड में देकर बिजली उत्पादक भी बना जा सकता है।

डेयरी उद्यमिता विकास योजना से सुखसागर की जिंदगी में आया बदलाव

- **प्रतिदिन 16 से 18 लीटर तक हो रहा दूध उत्पादन**
- **सुख सागर को प्रतिमाह 30 हजार रुपए तक हो रही आमदनी**
- **अनुदान लेकर उन्नत नस्ल की जर्सी एवं साहीवाल गाय खरीदा**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप पशुधन विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों के पशुपालकों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के किसान श्री सुखसागर यादव की आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है। उसे अब प्रतिमाह 30 हजार रूपए की आमदनी हो रही है।

सुखसागर यादव को राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना से 70 हजार रुपये का अनुदान मिला। इसके सहारे उन्होंने एक उन्नत नस्ल की जर्सी गाय और एक साहीवाल क्रॉस गाय खरीदी। पहले उनके पास सिर्फ एक देसी

गाय थी, जो प्रतिदिन लगभग 1 लीटर दूध देती थी और उसका उपयोग केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित था। उस समय पशुपालन से कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं होती थी।

लेकिन योजना का लाभ लेने के बाद अब उनके पास रोजाना 16 से 18 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। दूध बेचकर उन्हें हर महीने 25 से 30 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से नस्ल सुधार का भी लाभ उन्हें मिला है। इसके परिणामस्वरूप उन्नत नस्ल की बछिया और बछड़ा पैदा हुआ हैं।

पशुधन विकास विभाग द्वारा सुखसागर की गायों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कृमिनाशक दवाओं और मिनरल मिक्सचर की सुविधा के साथ बीमा सुविधा भी दी जा रही है। तकनीकी मार्गदर्शन भी समय-समय पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से सुखसागर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे आज एक सफल डेयरी उद्यमी के रूप में माना जा रहा है।

श्री रामलला दर्शन योजनाः आस्था संस्कृति और सामाजिक चेतना का संगम

जशपुरनगर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्री रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता का भी प्रतीक बन चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को अयोध्या में स्थित भगवान श्री रामलला के दर्शन का सुअवसर प्रदान करना है। योजना की औपचारिक शुरुआत 5 मार्च 2024 को रायपुर से हुई थी, जब मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं पहली ट्रेन को रवाना किया था।

जशपुर जिले में योजना प्रारंभ से अब तक 1632 रामभक्तों ने अयोध्या जाकर भगवान श्री राम का दर्शन लाभ ले चुके हैं। जिसमें जनपद पंचायत क्षेत्र जशपुर से 134 जनपद पंचायत क्षेत्र मनोरा से 95, जनपद पंचायत क्षेत्र बगीचा से 168, नगर पालिका क्षेत्र जशपुर से 83, नगर पंचायत क्षेत्र बगीचा से 58, जनपद पंचायत क्षेत्र कुनकुरी से 172, जनपद पंचायत क्षेत्र दुलदुला से 110, जनपद पंचायत क्षेत्र फरसाबहार से 179, नगर पंचायत क्षेत्र कुनकुरी से 109, जनपद पंचायत क्षेत्र पत्थलगांव से 220, जनपद पंचायत क्षेत्र कांसाबेल से 165 नगर पालिका क्षेत्र पत्थलगांव से 82 और नगर पंचायत क्षेत्र कोतबा से 57 रामभक्त अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन कर चुके हैं। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलता है, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहती है।

छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, यहां के लोग उन्हें भांचा राम के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री राम के प्रति आस्था प्रदेश के कण कण पर व्याप्त है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। दर्शन के बाद रामभक्तों के चेहरे पर झलकती संतुष्टि और आत्मिक खुशी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार के प्रति कृतज्ञता का भाव उनमें साफ झलकता है। श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और श्री राम के आदर्शों को सामाजिक चेतना में पुनः स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन रही है। ट्रेन रवाना करते समय बजते भजन, भगवान श्री राम की जयकारे की गूंज, यात्रियों के चेहरे से झलकती खुशी आस्था और सांस्कृतिक उत्सव का वातावरण रचते हैं।

श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा आध्यात्मिक अभियान है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में नए उत्साह और विश्वास का संचार कर रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई, जो उनकी दूरदर्शिता और लोककल्याणकारी सोच का जीवंत उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान के दर्शन कर चुके हैं। श्री रामलला दर्शन योजना केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के प्रति आस्था और उनके आदर्शों को अपने जीवन मूल्य में अपनाने की एक पहल भी है।

महतारी वंदन योजना से सरोज बनी आत्मनिर्भर, इस वर्ष तीज का पर्व बना खास

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार की महतारी वंदन योजना से उन्हें हर महीने सीधे खाते में आर्थिक सहायता मिल रही है, जिसके कारण वे आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कबीरधाम जिले के ग्राम चिमरा की महिला श्रीमती सरोज साहू के जीवन में इस बार तीज का त्यौहार खास बन गया है। कुछ समय पहले तक सरोज को घर के छोटे-छोटे खर्चों के लिए भी अपने पति से पैसे मांगने पड़ते थे। गांव की यात्रा हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी खर्च, हर बार उन्हें इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की, उनकी जिंदगी बदल गई। अब राशि सीधे उनके खाते में आती है, जिससे वे बिना किसी झिझक के अपनी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं।

प्रधानमंत्री सड़क बनने से मिली राहत, ग्रामीणों और किसानों का आना-जाना हुआ आसान

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में बहतराई से परसाही व्हाया बिजौर तक 6.400 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से हुआ है। इस सड़क ने क्षेत्र के ग्रामीणों को जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति दिला दी है। सड़क निर्माण से रहवासियों को आवागमन में सुविधा हो रही है। सड़क निर्माण से तीन गांवों के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है।

ग्रामीणों ने बताया कि पहले यह सड़क पूरी तरह गड्ढों से भरी और उखड़ी हुई थी। वर्ष 2023 में सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुआ, अच्छी गुणवत्ता और लगातार मेंटेनेंस के कारण सड़क अच्छी स्थिति में है। पहले बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी भरने से मार्ग और भी दुर्गम हो जाता था। स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार लोगों और शहर में कामकाज के लिए जाने वाले ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था।

स्थानीय किसान सहदेव कौशिक ने बताया सड़क बनने से हमें फसल शहर तक ले जाने में बहुत सुविधा होती है, पहले खराब रास्ते के कारण ट्रॉली और वाहन फँस जाते थे, जिससे समय और पैसा दोनों का नुकसान होता था। अब सीधा शहर से जुड़ाव हो गया है। वहीं छात्र युग भार्गव का कहना है कि अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़या और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो गया है। गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि यह सड़क उनके लिए ÷जीवन रेखा÷की तरह है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बन जाने से बहतराई, परसाही और बिजौर क्षेत्र के ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। आवागमन आसान हो गया है, समय की बचत हो रही है, और दुर्घटनाओं में कमी आ गई है साथ ही, किसानों को अपनी फसल बिना रुकावट के सीधे शहर तक ले जाने में अब सुविधा हो रही है।

भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का सपना देखा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 500 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 आबादी वाले गाँव) को हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है। इसके तहत सड़कों का न सिर्फ निर्माण किया जाता है, बल्कि उनकी देखरेख और रख-रखाव की भी जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि ग्रामीणों को लंबे समय तक सुविधा मिल सके।

‘सरगुजा 30’ सेंटर पहुचे कलेक्टर, बच्चों से किया आत्मीय संवाद

रायपुर। राज्य के सरगुजा जिला के अम्बिकापुर स्थित मल्टी पर्पस परिसर में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के मार्गदर्शन हेतु संचालित ‘सरगुजा 30’ निःशुल्क कोचिंग सेंटर कलेक्टर सरगुजा पहुंचकर बच्चों से आत्मीय संवाद किया । उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी पढ़ाई की प्रगति, पुस्तकों की उपलब्धता, छात्रावास की सुविधा तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों का प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक होता है और उसके लिए निरंतर लगन से परिश्रम करना आवश्यक है। कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने छात्रों को

समय का सदुपयोग करने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए आत्मविश्वास और लगन से पढ़ाई करने को प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने उपस्थित शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलनी चाहिए।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतियोगी परीक्षा के मार्गदर्शन हेतु संचालित ‘सरगुजा 30’ निःशुल्क कोचिंग सेंटर शिक्षकगण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

8 स्कूलों के नवीन भवन निर्माण के लिए 6.19 लाख रूपये की स्वीकृति

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सार्थक पहल से रायपुर सी.एस.पी.टी.सी.एल द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के संचालन हेतु जिले के विभिन्न संचालित 8 स्कूलों के नवीन भवन निर्माण कार्य के लिए 6 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सी.एस.आर. मद अंतर्गत आर.टी.जी.एस. व एन.ई.एफटी. के माध्यम से राशि प्राप्त हुआ है। उक्त राशि में से 6 करोड़ 19 लाख रूपए के 08 नवीन भवन निर्माण हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जशपुर को निर्माण एजेंसी नियुक्ति कर कार्य कराने हेतु राशि दी गई है। इनमें कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बांसबहार में शासकीय प्राथमिक शाला तुरंगाखार नवीन भवन के लिए 20 लाख, फरसाबहार विकासखण्ड के ग्राम पंचायत गारीघाट में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य बागमाड़ा के लिए 20 लाख, ग्राम पंचायत पण्डरीपानी में उच्च माध्यमिक विद्यालय बालक पण्डरीपानी में नवीन भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख एवं ग्राम पंचायत कंदईबहार में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंदईबहार में नवीन भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख, बगीचा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत टटकेला में हाईस्कूल टटकेला में 75 लाख 23 हजार, कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत गिनाबहार में नवीन भवन निर्माण कार्य प्राथमिक शाला खजूरबहार के लिए 20 लाख, लोधमा में हायर सेकेण्डरी स्कूल लोधमा के लिए 1 करोड़ 21 लाख 16 हजार एवं दुलदुला विकासखण्ड के हायर सेकेण्डरी स्कूल दुलदुला में नवीन भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहान योजना से अनीता के सपनों को मिली उड़ान

■ सब्जी की खेती से कमा रही ढाई लाख रुपए सालाना

रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित बिहान योजना आशा की किरण बन रही है। इसी योजना ने मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत कंतेली के सुरदा गांव की अनीता पटेल के जीवन को नई दिशा दी है। अनीता पटेल के पास महज 01 एकड़ जमीन थी। पति और तीन बच्चों के साथ उनका जीवन काफी कठिनाईयों में गुजर रहा था। आय कम होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी संकट में पड़ गई थी। ऐसे में शासन की बिहान योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी।

अनीता ने ÷मां शाकम्भरी स्व सहायता समूह÷ का गठन किया। समूह को 15 हजार रुपये की चक्रीय निधि और 60 हजार रुपये का सामुदायिक निवेश कोष मिला। इस राशि का उपयोग कर उन्होंने सब्जी की खेती शुरू की। खेती का दायरा बढ़ा तो बैंक से शासन की मदद से 01 लाख रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया गया। अनीता पटेल अपनी बाड़ी में ग्राफ्टेड मिर्ची, भाटा और अन्य सब्जियां उगाकर सालाना लगभग ढाई लाख रुपये की आय कमा रही हैं। मुंगेली मंडी नजदीक होने से उन्हें सब्जियों की बिक्री आसान हो जाती है और नगद भुगतान भी मिल जाता है।

अनीता ने बताया कि ÷बिहान योजना'' से जुड़कर न केवल परिवार चलाना आसान हुआ, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई है। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। अनीता ने इस सहयोग के लिए कलेक्टर सहित शासन-प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अब उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के सपनों को सच करने की राह आसान हो गई है।

स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बनकर दूसरी महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बिहान योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों की महिलाएँ आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। कांसाबेल विकासखंड की रीमा स्व सहायता समूह इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। लगभग आठ वर्षों से सक्रिय यह समूह शुरुआती दौर में मात्र 100-100 रुपये की मासिक बचत से शुरू हुआ था, लेकिन आज यह 35 शासकीय स्कूलों को मध्यान्ह भोजन के लिए राशन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती सविता चौहान ने बताया कि इस कार्य से हर वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक की आय हो रही है, जिससे सभी 10 महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। समूह ने 1.5 लाख रुपये का ऋण लिया, जिसे सदस्यों ने अपने निजी जरूरतों में उपयोग कर अपनी आजीविका को और सुदृढ़ किया।

बीमारी से जीवन फंसी संकट में, मुख्यमंत्री साय ने सहायता के लिए बढ़ाया हाथ

जशपुरनगर । परिवार के किसी एक सदस्य के गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाने से पूरा परिवार संकट में आ जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना उपचार में सहयोग बनता है। इसके तहत हितग्राहियो को 5 लाख तक के निशुल्क उपचार की सुविधा सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में मिलती है। लेकिन जब गंभीर बीमारी के उपचार और सर्जरी का खर्च आयुष्मान योजना की सीमा से अधिक हो जाए तो क्या होगा? कहां से आएगा इलाज के लिए लाखों रुपये? संकट की ऐसी घड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपत्ती में फंसे ऐसे परिवारों की सहायता के लिए फिर हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत जिले के 72 मरीजों को उपचार के 2 करोड़ 85 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि संबंधित अस्पताल के बैंक खाते में चेक या एनईएफटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। इस राशि से लाभार्थी कैंसर,बोनमेरो ट्रांसफर,किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे उपचार बड़े अस्पतालों में करा सके। समय पर आर्थिक सहायता

मिल जाने से न केवल मरीजों का जीवन सुरक्षित हो पाया अपितु परिवार को भी बड़ी राहत मिली। इस सहायता के लिए मरीज और उसका परिवार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जता रहा है।

इस तरह प्राप्त करें सहायता

सीएमएचओ डॉ जी एस जात्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है। यह आवेदन पत्र सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके आवेदन के साथ मरीज का आधार कार्ड, बीमारी से संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज, जिस अस्पताल में उपचार कराना चाहते हैं वहाँ का प्राकलन रिपोर्ट (स्टीमेट) संलग्न करना होता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा है सुधार

उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार और सुधार की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा होने के साथ इसके लिए बजट भी सरकार जारी कर चुकी है। जमीन चयन होने के साथ कॉलेज शुरू करने की कवायद चल रही है। अस्पतालों में भौतिक और मानव संसाधन जुटाया जा रहा है।

तारा बाई ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिशाल

बीसी सखी बनकर गांवों तक पहुँचा रही बैंकिंग सेवाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य लगातार जारी है। ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत महिलाओं को समूहों में संगठित कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे रोजगारोन्मुखी कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।

इसी कड़ी में जशपुर जिले के विकासखंड कांसाबेल के छोटे से ग्राम चिड़ोरा की तारा बाई ने प्रज्ञा स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। समूह सहेली ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद उन्होंने बीसी सखी का कार्य शुरू किया। चिड़ोरा गांव मुख्य मार्ग से न जुड़ा होने के कारण ग्रामीणों को बैंकिंग लेन-देन के लिए कांसाबेल तक जाना पड़ता था। लेकिन तारा बाई ने बैंकिंग सेवाएं गांव तक पहुँचाकर ग्रामीणों की सच्ची सखी बनने का काम किया है।

आज गांव के लोगों को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मनरेगा मजदूरी भुगतान, स्वयं सहायता समूहों की राशि का लेन-देन और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए अब बैंक शाखा तक नहीं जाना पड़ता। ये सभी सेवाएं तारा बाई के माध्यम से गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। तारा बाई बताती हैं कि अब तक वे प्रतिमाह 50 से 60 लाख रुपये का लेन-देन कर रही हैं और इसके माध्यम से उन्हें 8 से 9 हजार रुपये मासिक आय हो रही है। इस आय से वे न केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं।

राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना से सुखसागर आर्थिक रूप से हुआ मजबूत

- योजना से 70 हजार के अनुदान का लाभ लेकर उन्नत नस्ल की जर्सी एवं साहीवाल क्रास गाय खरीदा
- 16 से 18 लीटर तक हो रहा दूध उत्पादन,
- सुख सागर को माह में 30 हजार रुपए तक हो जाता है आमदनी

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप पशुधन विकास विभाग द्वारा जिले के गौव पालकों को विभागीय योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बगीचा विकासखण्ड के श्री सुखसागर यादव को राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत नस्ल सुधार योजना का लाभ दिया गया है।

बगीचा विकासखण्ड के पशुधन विकास विभाग द्वारा हितग्राही सुखसागर यादव को राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ दिया गया एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत नस्ल सुधार किया गया। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से 70 हजार के अनुदान का लाभ दिया गया एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत नस्ल सुधार किया गया। हितग्राही सामान्य किसान है, इनका रोजगार का कार्य खेती था। योजना का लाभ लेने के पूर्व हितग्राही के पास 01 देसी गाय थी। इनकी गाय उस समय लगभग प्रतिदिन 1 लीटर दूध देती थी। जिसका उपयोग घर में ही कर लिया जाता था।

पशुपालन से कोई अतिरिक्त आय नही होती थी। पशुधन विकास विभाग से राज्य डेयरी उद्यमिता विकास अंतर्गत हितग्राही द्वारा शासकीय योजना का लाभ लेकर 01 उन्नत नस्ल की जर्सी गाय और एक साहिवाल क्रॉस गाय खरीदा गया । वर्तमान में कुल 16-18 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। जिसके विक्रय से हितग्राही को राशि रूपये 25000-30000 रूपये मासिक आमदनी प्राप्त हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नस्ल सुधार योजना द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का लाभ लिया जाता है। जिससे वर्तमान में उन्नत नस्ल की बछिया एवं बाछा उत्पन्न हुई है। पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ लेने के पश्चात् हितग्राही के आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। विभाग द्वारा समस्त गाय का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। कृमि नाशक दवाइयां एवं मिनरल मिक्सचर प्रदान किया जाता है। आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

कौशल विकास प्रशिक्षण से युवाओं को मिला रोजगार के बेहतर अवसर

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश के छात्र-छात्राओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला जशपुर के लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में संचालित नवगुरुकुल शिक्षण संस्थान के माध्यम से बारहवीं उत्तीर्ण छात्राओं तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने की इच्छुक युवतियों को बिजनेस एवं टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को हॉस्टल, भोजन एवं लैपटॉप जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियाँ भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें।

कुनकुरी की कुमारी नेहा खाखा ने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद नवगुरुकुल में प्रवेश परीक्षा पास कर फाइनेंस स्किल प्रोग्राम जॉइन किया। एक वर्ष के अध्ययन उपरांत आज वे इसी संस्थान में एसोसिएट टीचर के रूप में कार्यरत हैं और प्रतिमाह रू 15,000 का वेतन प्राप्त कर रही हैं।

वे कहती हैं कि "नवगुरूकुल ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यहाँ आकर मैंने एआई फीचर और गूगल शीट जैसे आधुनिक टूल्स को सीखा। आज मैं न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हूँ बल्कि अन्य छात्राओं को पढ़ाकर उन्हें भी आगे बढ़ा रही हूँ।"

कवर्धा अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा, महज एक माह के भीतर 145 मरीजों को मिला लाभ

- मुख्यमंत्री की मंशा और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के अनुसार जिला बनने के बाद पहली बार मिली है बड़ी सौगात

रायपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जयसवाल के निर्देश पर कबीरधाम जिले को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। जिला बनने के बाद पहली बार कबीरधाम जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ की गई है। 25 जुलाई 2025 को इस सुविधा का शुभारंभ हुआ और महज एक माह से भी कम समय में लगभग 145 मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। अब तक कबीरधाम जिले के लोगों को सीटी स्कैन जैसी जांच के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। इसमें समय और धन दोनों की दिक्कत होती थी। लेकिन अब यह सुविधा शासकीय जिला अस्पताल में उपलब्ध होने से जरूरतमंद मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ केशव ध्रुव ने बताया कि महज एक माह से भी कम समय में लगभग 145 मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। अब तक सीटी स्कैन जांच का लाभ विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों ने उठाया है जिसमें पंडरिया ब्लॉक से 22 मरीज,बोड़ला से 35 मरीज, सहसपुर लोहारा से 25 मरीज, कवर्धा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 50 मरीज अन्य जिलों से 13 मरीज । इनमें से 14 मरीजों का स्कैन आपातकालीन स्थिति में किया गया, जो मरीजों के उपचार में बेहद सहायक साबित हुआ।

नहीं बुझेगी साठ साल पुराने परसदा विद्यालय में शिक्षा की ज्योति, रिक्त पद पर शिक्षक की हुई नियुक्ति

- युक्ति युक्तकरण से विद्यालय को मिला शिक्षक, विद्यार्थियों की पढ़ाई हुई आसान

कोरबा । इस गाँव के पाठशाला की दीवारे बदल गई है। छत भी बदल गया है लेकिन पाली ब्लाक के अंतर्गत ग्राम परसदा का पाठशाला जिस जगह पर लगता था आज भी वही लगता है। बीते छह दशक से भी ज्यादा पुराने इस विद्यालय में शिक्षा की ज्योति अनवरत जल रही है। समय के साथ पदोन्नति के बाद विद्यालय में जब पद रिक्त हुए तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने विद्यार्थियों की भविष्य को बेहतर बनाने के लिए स्कूल खुलने से पहले युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया अपनाई उससे वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियमित शिक्षको की नियुक्ति सम्भव हो पाई।

पाली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम परसदा के प्राथमिक शाला की पहचान बहुत पुरानी है। वर्ष 1964 से संचालित इस गाँव के स्कूल में पढ़ाई कर बहुत से विद्यार्थियों ने अपना बेहतर भविष्य बनाया। समय के साथ विद्यालय के जर्जर भवन को संवारकर ठीक किया गया। विद्यालय में वर्षों से शिक्षक के पद खाली थे। जिससे यहाँ पढ़ाई करने वाले 46 विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती थी। इस सत्र में राज्य शासन द्वारा की गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से विद्यालय को नियमित शिक्षक मिल गया है। यहाँ शिक्षक के रूप में श्री रूपेश कश्यप की नियुक्ति हुई है। कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाई कराते हुए शिक्षक रूपेश कश्यप ने बताया कि वे युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के बाद इस विद्यालय में पदस्थ हुए हैं और खुश भी है। उन्होंने बताया कि हमारे गाँव का यह विद्यालय बहुत पुराना है और यहाँ से पढ़ कर बहुत से लोग शिक्षित हुए। विद्यालय में प्रधान पाठक की जिम्मेदारी श्री जी डी बंजारे सम्हाल रहे हैं। विद्यालय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों अभिषेक राजपूत, नीतेश और अनुराग राजपूत सहित छात्रा हिना,अनामिका,आदिति, दीपल सभी खुश है। वे बताते हैं कि गुरुजी के आ जाने से अब हमारा क्लास नियमित लगता है। वे हमें पुस्तक पढ़ाने के साथ खेल भी खिलाते हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में गुरुजी की कमी कई वर्ष से बनी हुई थी। अब नए गुरुजी के आ जाने से हमें भी बढ़िया लगता है। इसी तरह ग्राम परसदा के लाइनपारा में 34 विद्यार्थी दर्ज है। यहाँ शिक्षिका श्रीमती नेमी जायसवाल युक्ति युक्तकरण से पदस्थ हुई है। एकल शिक्षकीय इस विद्यालय में पढ़ने वाली मानसी और पायल तथा पुनिशा ने बताया कि मैडम के आने के बाद नियमित कक्षा लगती है। विद्यालय के प्रधानपाठक श्री नोहर प्रसाद साहू ने बताया कि युक्ति युक्तकरण से शिक्षिका के आने से विद्यार्थियों के साथ ही उन्हें भी सहूलियत हुई है।

नई सहकारिता नीति : लोकसभा में बोले शाह- यह सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास का रोडमेप

- केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि, केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से 24 जुलाई 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 की घोषणा की है। यह नीति सहकारी संस्थाओं के व्यवस्थित और समग्र विकास के लिए एक व्यापक ढांचा और रोडमैप प्रदान करती है।

मंत्री ने बताया कि इस नीति का मुख्य मिशन अगले दस वर्षों में 16 प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करना है। इन्हें छह रणनीतिक मिशन स्तंभों में विभाजित किया गया है। खास बात यह है कि नीति के अधिकांश बिंदुओं पर अमल की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। नीति के तहत पहला मिशन सहकारिता को मजबूती देने के लिए अनुकूल कानूनी और विनियामक वातावरण तैयार करना है, जिससे समितियों को अधिक स्वायत्तता, सुशासन और पारदर्शिता मिल सके। दूसरा मिशन सहकारी समितियों को अन्य आर्थिक संस्थाओं की तरह सुलभ और किफायती वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है।

पेशेवर प्रशिक्षण तंत्र विकसित करने का प्रावधान : इसके अतिरिक्त नीति में सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन और पेशेवर प्रशिक्षण का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत युवाओं को सहकारी उद्यमों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना, मानकीकृत सहकारिता पाठ्यक्रम तैयार करना और प्रशिक्षकों व विजिटिंग फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार का मानना है कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 से सहकारी समितियां भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगी और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएंगी।

सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान

तीसरे स्तंभ में सहकारी समितियों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने, उनके ढांचे को मजबूत करने और भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। चौथा मिशन समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग, पेशेवर प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। नीति का पांचवां स्तंभ समावेशिता और सदस्य-केंद्रितता को बढ़ावा देना है, ताकि सहकारी आंदोलन देश के हर कोने तक पहुंचे और युवाओं व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। छठा मिशन सहकारी समितियों की नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से की भेंट

- बस्तर में स्थानीय आदिवासियों के सर्वांगीण विकास और इको टुरीज्म को लेकर चर्चा
- वनमंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव को दिया बस्तर आने का न्यौता

रायपुर। प्रदेश के वनमंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय दिल्ली प्रवास पर गए, जहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नति को लेकर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। वनमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में हो रहे कार्य, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 सहित हाथी मानव द्वन्द को लेकर जानकारी प्रदान करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने आवश्यक मांगों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का ध्यान आकृष्ट किया है।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास, वन आधारित रोजगार पर चर्चा

केंद्रीय वनमंत्री से भेंट को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर जिला नक्सल मुक्त हो चूका है। जहाँ के आदिवासियों, युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बस्तर सार्वधिक वन अच्छादित क्षेत्र है। जहाँ वन आधारित उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार से जोडा जा सकता है। साथ ही इंद्रावती, कांगेर घाटी, तीरथगढ़ चित्रकोट जैसे अन्य स्थानों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पर स्थापित करने के उद्देश्य भारत सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से इको टुरीज्म को बढ़ावा देने विस्तृत चर्चा की।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव को दिया बस्तर आने का न्यौता

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव को बस्तर की वर्तमान स्थिति और वहां की जरूरतों के बारे में जानकारी देते हुए बस्तर प्रवास के लिये आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण बस्तर का विकास विष्णुदेव साय सरकार का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने ले लिये भाजपा की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। मंत्री कश्यप ने कहा कि केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में आदिवासियों और युवाओं के विकास को लेकर गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार का लाभ निश्चित मिलेगा।

सुकमा नगर पालिका परिषद को विशेष श्रेणी पुरस्कार

स्वच्छता संगम 2025 में मुख्यमंत्री के हाथों मिला सम्मान

रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान करते हुए, सुकमा नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बस्तर संभाग स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। स्वच्छता के विविध आयामों-शिकायत निवारण की त्वरित व्यवस्था, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, शहर की सौंदर्यपूर्ण स्वच्छता तथा नागरिकों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर परिषद को ÷विशेष श्रेणी पुरस्कार÷ से सम्मानित किया गया है।

स्वच्छता संगम 2025 के भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने सुकमा नगर पालिका परिषद की सराहना करते हुए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। परिषद की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री पी.आर. कोर्राम, नपा उपाध्यक्ष श्रीमती भुवनेश्वरी यादव तथा स्वच्छता दीदियों ने मंच पर पहुंचकर यह सम्मान ग्रहण किया। यह अवसर सुकमा जिले के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक बन गया।

जिला कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने इस उपलब्धि पर नगर पालिका परिषद की टीम, स्वच्छता दीदियों, सफाई कर्मियों तथा नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार निरंतर परिश्रम, पारदर्शी कार्यप्रणाली और जनसहभागिता का प्रतिफल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में सुकमा जिला स्वच्छता के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करेगा और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। सुकमा की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि इच्छाशक्ति, सामूहिक प्रयास और नागरिकों के सहयोग से किसी भी नगर को स्वच्छता के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। सुकमा का यह प्रदर्शन न केवल बस्तर संभाग के अन्य नगरीय निकायों, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक छग राज्य सहकारी संघ रायपुर द्वारा मयंक ऑफसेट रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail: cgcoopnews@gmail.com